



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 16 मार्च, 1989/25 फाल्गुन, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचि).—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल (जुगेहड़, मौजा बण्डी) तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव: एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी

(नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक, उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला: कांगड़ा :

तहसील:-कांगड़ा:

महाल वण्डी	खसरा नं 0 1	क्षेत्रफल हक्केयरों टेरर में 3	1	2	3	4	5
			96	0	08	09	
जूगेहड़, मौजा	464/3/1	0 07 24	545199	0	00	75	
	465/3/1	0 20 32	100	0	02	78	
	467/3/1	0 03 14	101	0	00	40	
	513/489/1	0 03 99	102	0	07	67	
	514/489/1	0 09 98	1031	0	09	75	
	4/1	0 82 77	1041	0	10	23	
	4/2	0 01 44	1141	0	01	92	
	519/51	4 96 17	54611151	0	01	66	
	80	0 07 48	1201	0	00	49	
	81	0 06 51	12112	0	00	10	
	82	0 19 52	12212	0	02	38	
	83	0 06 30	12412	0	02	13	
	84	0 06 08	125	0	19	13	
	85	0 04 72	126	0	24	46	
	86	0 05 24	127	0	05	95	
	87	0 03 71	128	0	02	08	
	530/90	0 03 45	1281	0	02	38	
	531/90/1	0 02 41	12812	0	02	20	
	532/91	0 01 20	55212911	0	40	95	
	533/91/1	0 05 47	55212912	0	34	71	
	534/92	0 01 60	553129	0	04	74	
	535/92	0 12 61	554130	0	02	18	
	536/92	0 11 40	556130	0	01	49	
	537/93	0 03 06	558130	0	02	94	
	538/93	0 03 08	131	0	02	28	
	539/93	0 03 04	132	0	05	92	
	540/93	0 03 10	1331	0	09	23	
	541/93	0 03 08	13312	0	05	44	
	542/95	0 12 62	134	0	05	79	
	543/95	0 10 19	135	0	02	64	
	77	0 06 50	136	0	03	84	

1	2	3	1	2	3
137	0	16 19	159	0	20 82
138	0	03 93	160	0	10 50
139	0	02 50	161	0	04 96
140	0	01 08	163	0	01 35
141	0	26 24	164	0	01 71
142	0	03 75	165 11	0	03 58
143	0	01 45	166	0	00 58
144	0	06 32	167	0	05 18
145	0	01 58	169 11	0	03 30
146	0	03 42	170 11	0	02 62
147	0	05 50	557 17 11	0	04 22
148	0	03 94	172 11	0	00 48
149	0	02 04	173 11	0	01 22
150	0	03 64	175 12	0	04 75
151	0	06 61	176 11	0	00 22
152	0	04 99	177 12	0	00 48
153	0	02 16	178 12	0	06 39
154	0	06 79	179 12	0	03 08
155	0	22 54	214 12	0	02 84
156	0	00 56			
157	0	01 19	कुल कित्ता.. 107	12	19 13
158	0	07 83			

शिमला-171002, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88—पर्यटन (सचिव) :—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल रिच्छाल, मीजा वण्डी, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अतिआवश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है। उक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि का अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अतिआवश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवम् भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व, भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी			1	2	3
जिला: कांगड़ा	तहसील: कांगड़ा	क्षेत्रफल हैक्टेयरों में	789	0 03	61
महाल	खसरा नं०	3	790	0 01	80
1	2		791	0 00	27
			79211	0 61	89
			79311	0 18	83
स्त्रिघाट, मौजा वण्डी।	73812	0 00 22	950	0 21	02
	74312	0 05 34	951	0 07	00
	74411	0 19 91	952	0 07	04
	75411	0 00 41	953	0 16	32
	748	0 37 71	954	0 00	46
	75111	0 26 42	955	0 00	23
	76011	0 04 04	956	0 00	36
	76111	0 04 25	957	0 00	30
	762	0 02 07	958	0 00	64
	763	0 06 08	960	0 87	08
	764	0 06 36	961	0 00	76
	765	0 03 11	962	0 03	92
	766	0 02 72	963	0 04	68
	767	0 00 80	96411	0 07	51
	768	0 06 81	96511	0 14	51
	769	0 08 56	966	0 00	72
	770	0 12 90	967	0 00	38
	771	0 06 93	96811	0 01	08
	772	0 01 52	97011	0 00	38
	773	0 02 78	97811	0 00	70
	774	0 02 16	97911	0 01	15
	775	0 13 62	98011	0 00	12
	776	0 00 52	105111	0 01	56
	777	0 03 45	105211	0 00	50
	778	0 05 41	105311	0 01	21
	779	0 05 60	105412	1 33	22
	780	0 14 82	1055	0 31	13
	781	0 13 01	1056	0 17	23
	782	0 08 21	105711	0 14	43
	783	0 16 23	106011	0 03	98
	784	0 14 74	106211	0 12	10
	786	0 02 21	106811	0 02	59
	78712	1 57 06			
	788	0 01 44 कुल किता	71	8 48	36

शिमला-2, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यंटन (सचिव)।—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल सनौरा, मौजा दुगियारी, तहसील व जिला कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अत्यावश्यक अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित विषया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व, भूमि का कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यलय में निरीक्षण किया जा सकता है।

## विवरणी

जिला : कांगड़ा

तहसील : कांगड़ा:

महाल	खसरा नं 0	अतेकफल हैक्टेयरों में			1	2	3
		1	2	3			
सनौरा	434/1	0	02	92	450	0	00 15
	435	0	00	52	451	0	00 25
	436	0	00	32	452	0	00 60
	437	0	00	62	453	0	01 47
	438/1	0	00	54	822/454	0	02 49
	439/1	0	00	04	823/454	0	02 43
	440	0	00	80	455/1	0	06 99
	441	0	00	15	456/1	0	08 31
	442	0	02	35	457	0	00 55
	443	0	01	01	458	0	00 35
	444	0	01	88	459	0	00 20
	445	0	02	86	460	0	00 51
	446	0	02	41	461	0	00 66
	447	0	00	66	462	0	00 42
	448	0	00	39	463	0	01 40
	449	0	00	28	464	0	00 50
					465	0	00 66
					469/1	0	00 12
					470/1	0	05 57
					471	0	01 26

1	2	3	1	2	3
	472	0 00 30		511	0 01 72
	473	0 01 60		512	0 02 66
	474	0 03 39		513	0 00 40
	475/1	0 03 09		514	0 01 26
	485	0 07 25		515	0 00 09
	488/1	0 16 16		516	0 01 98
	489	0 01 94		517	0 02 88
	490	0 21 16		518	0 03 87
	491	0 00 80		519	0 04 34
	492	0 22 78		520	0 02 85
	493	0 01 32		521	0 02 24
	494	0 10 39		522	0 01 64
	824/495	0 07 73		523	0 04 16
	825/494	0 11 41		524	0 03 79
	496	0 00 48		525	0 01 23
	497	0 00 39		526	0 02 28
	498	0 13 33		528	0 00 42
	499	0 14 77		529	0 41 04
	501	0 01 20		533	0 01 08
	502	0 00 35		558/1	0 00 39
	503	0 00 50		559/1	0 00 06
	504	0 00 16		580/1	0 00 58
	505	0 01 02		583/1	0 00 09
	507	0 01 47		586/1	0 04 21
	508	0 02 06		587/1	0 00 42
	509	0 01 90		584/1	0 00 09
	510	0 01 05	कुल कित्ता..	89	2 86 41

## गिमला-2, 10 मार्च, 1989

संख्या 6-37/88-पर्यटन (सचिव)।—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः महाल भेड़ी, मौजा वड़ो, तङ्सीत व जिना कांगड़ा में हवाई पतन (एयरपोर्ट) गगल के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अतिग्रावश्यक अपक्रित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन इस से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हैतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन उर मण्डन, अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा को उक्त भूमि को अर्जन करने के आदेश लेने का एहत द्वारा निर्देश दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि अतिआवश्यक मामला होने के कारण उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधी समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि पर कब्जा ले सकता है।

भूमि का रेखांक उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) एवं भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

जिला : कांगड़ा

तहसील : कांगड़ा

महाल	खसरा नं०	क्षेत्रफल हैक्टरों में		
भेड़ी, मौजा वण्डी	13/1	0	07	11
	54/1	0	00	42
	55/1	0	10	56
	56/1	0	09	03
	57/1	0	04	22
	66/1	0	01	36
कुल कित्ता ... 6		0	32	70

आदेश द्वारा,  
ए० इन० विद्यार्थी,  
वितायुक्त एवं सचिव।

